श्री चतुर्भुज (झालावाड़) : सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है। चने का भाव 235 दिलवाने का वायदा किया था और 225 दिलवा रहे हैं। राजस्थान में अभी दिलवाना प्रारम्भ भी नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : हो गया।

(व्यवधान)**

12.14. hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported disruption of Telephone system in Delhi and other parts of the country

SHRI JAGPAL SINGH (Hardwar) : I call the attention of the Minister of Communications to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :

> "Reported disruption of telephone system in Delhi and other parts of the country and action taken by Government in regard thereto."

12.15. hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

THE MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI V.N. GADGIL) : On Account of the torrential rains on Friday, 15th April, 1983 and some showers on Saturday, the 16th April, 1983, telephone cables in several parts of Delhi were affected. At the same time, junction cables interconnecting different exchanges were also affected with the result that telephone communications for even those subscribers whose telephones were not affected was hampered.

The intensity of the rain was unprecedented. It has been reported in News Paper that rain fall was an all time record for Delhi for the month of April. Moreover the intensity of untimely rain was concentrated for a period of 2-30 hours resulting in unprecedented water logging in the city.

Nearly 21,000 telephones in Delhi were reported to be faulty due to cable break downs in the various exchange areas. 56 junction cables connecting different exchanges were also faulty. By utilising all the available resources about 20,000 telephone connections and 53 junction cables have been restored fully as on 26th evening. Restoration work of remaining 1,000 telephone lines and 3 junction cables is in progress. They are likely to be set right by today evening. Following measures, short and long term, for averting cable break downs are being taken :—

(i) pressurisation of main cables.

(ii) Laying of new cables duly pressurised.

(iii) providing protection to the underground cables by way of half ducts wherever the depth of cable warrants this.

(iv) laying of new junction and primary cables in ducts.

(v) flooding of cable trenches before they are closed. This is to detect faults in the cables well in advance of monsoon.

(vi) use of jelly filled cables in distribution cable network.

In Bombay due to rain about 1,000 subscribers were affected due to cable break downs on 15th April, 83. These have all been set right except a few.

There are no other serious break downs in the country due to rains.

श्री जगपाल सिंह : उपाध्यक्ष जी, जिस समस्या पर आज आप ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

**Not recorded.

स्वीकार किया है, इस पर सदन में पहले कई बार चर्चा हो चुकी है और चर्चा होने के बाद भी कई बार हमारे संसद सदस्यों ने ज़ीरो-आवर में भी इस समस्या को लेकर यहां पर काफी हंगामा किया है, लेकिन आज तक माननीय मन्त्री जी और यह सरकार यहां की टेलीफोन व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाये हैं।

माननीय मन्त्री जी द्वारा अभी जो जवाब दिया जा रहा था उसमें वर्षा का कारण है, पिछले सप्ताह यहां पर जो भारी वर्षा हुई उस भारी वर्षा के कारण हज़ारों टेलीफोन डेड हो गये। टेलीफोन ही नहीं, मैं माननीय मन्त्री जी को यह बतलाना चाहूंगा कि आप ने तो अपने उत्तर में सिर्फ टेलीफोन्ज़ का ही ज़िक्र किया है, बल्कि दिल्ली के कई टेलीफोन एक्सचेन्ज बिल-कुल खत्म हो चुके हैं, जिससे कोई भी टेलीफोन का कनेक्शन जुड़ नहीं पाया। आपके डिपार्टमेंट के लोगों ने आप को रिपोर्ट दी होगी, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है—20, 22, 56 नम्बर के तथा कुछ अन्य एक्सचेन्जों में टेलीफोन की सम्पूर्ण व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई है, बल्कि टेलीफोन एक्सचेन्ज ही खत्म हो गये हैं जिन से टेलीफोन का कनेक्शन नहीं जुड़ पाया है। मैं यह तो मान सकता हूं कि बारिश की वजह से टेलीफोन खराब हो जाय, लेकिन आप के प्लांट्स तो ज़रा सी ज्यादा बारिश होने से, ज़रा सी ज्यादा गर्मी पड़ने से बेकार हो जाते हैं, वे इतने पुराने हो गये हैं कि आप से ठीक नहीं हो पा रहे हैं। आप की यह भी नीति है कि बड़े शहरों का प्लांट ज़रा पुराना हुआ, उस को छोटे शहरों में चेन्ज कर देते हैं। जिसका नतीजा यह होता है कि वे प्लांट छोटे शहरों में जाकर काम नहीं कर पाते हैं।

दिल्ली देश की राजधानी है, यहां पर ज्यादा बारिश होने से या ज्यादा गर्मी पड़ने से आप के टेलीफोन एक्सचेन्ज के प्लांट खत्म हो जाएं या चल न पाएं, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हमारी नीति में कोई कमी है···

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सब जगह यही हाल है।

श्री जगपाल सिंह : यह मामूली बात नहीं है। जिस समस्या पर आज मैं बोल रहा हूं यह कोई मामूली समस्या नहीं है। यह स्थिति उस समय है जब कि हमारे देश में इस उद्योग में काम करने वालों का परसेन्टेज दुनिया के हर मुल्क से ज़्यादा है, हर मुल्क के मुकाबले इस उद्योग में ज़्यादा कर्मचारी लगे हुए हैं। इसके बारे में मैं बाद में बतलाऊंगा लेकिन यह मामूली समस्या नहीं है। इससे हमारी पूरी अर्थ-व्यवस्था, राज-नीति, सामाजिक व्यवस्था, देश की एकता, यानी हर चीज इस साधन से जुड़ी हुई है। अकाली आन्दोलन, असम की समस्या, नागा, मीज़ो, मणिपुर तथा अन्य जो समस्यायें हैं उन सबका सम्बन्ध इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन दुख की बात है कि 35 साल की आज़ादी के बाद भी यह सरकार एक सुचारू कम्यूनिकेशन व्यवस्था इस देश को नहीं दे पाई है।

70 साल के इतिहास में हमारा टेलीफोन सिस्टम इतना खराब हो गया है कि आज दुनिया में कहीं भी इतना खराब नहीं है। यहां तक कि जो अन्डर डेवलप्ड कन्ट्रीज हैं, उन के यहां भी इतनी खराब व्यवस्था टेलीफोनों की नहीं है। मैं इस समस्या पर यह चीज़ भी लाना चाह रहा हूं कि अभी राय-बरेली के अन्दर प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आई० टी० आई० की एक फैक्टरी लगाई और बल्जियम से फैक्टरी के बारे में एग्रीमेन्ट हुआ। बेल्जियम की एक फैक्टरी ने उस में हिस्सेदारी करके सहयोग देने की बात की है। मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या दुनिया के किसी और देश ने भी हमारी राय-बरेली की उस फैक्टरी को टेक्नोलाजी देने के लिए कोई आफर दी थी ? मुझे मालूम है कि दूसरी फैक्टरियों की तरफ़ से भी आफर आई थी लेकिन माननीय मंत्री जी इस सदन में स्वीकार कर चुके हैं कि जो क्रोस वार राय-बरेली फैक्टरी में बनाई जा रही हैं, वे

पुरानी टेक्नोलाजी से बनाई जा रही हैं और वहां पर जो 2 लाख क्रौस बार बनाने की बात थी, उतना उत्पादन वहां पर नहीं हुआ है। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि जो क्रोस बार वहां पर बनेंगी हमारी सरकार चाहे उन से संतुष्ट हो जाए लेकिन उनसे हमारे टेलीफोन एक्सचेन्जों का काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि 80 करोड़ रुपये प्रति वर्ष हमारी सरकार टेलीफोन के साधन बाहर से आयात करने पर खर्च करती है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो आपने 12 एलेक्ट्रोनिक प्लान्ट दिल्ली के अन्दर लगाने की बात कही थी, जिनसे करीब 2 लाख टेलीफोन ग्राहकों को सुविधा मिलने वाली थी, आज तक उन प्लान्टों को लगाने की बात नहीं हुई है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उसने 12 इलेक्ट्रोनिक प्लान्ट बाहर से आयात किये हैं या नहीं और अगर नहीं किये हैं, तो कब तक दिल्ली में उनको लगाने का विचार वह कर रही है ?

इस सारी व्यवस्था के गड़बड़ होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी राजनीतिक इच्छा इतनी सुदृढ़ नहीं है इस सारी व्यवस्था को सुधारने के लिए और इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अधिकारीगण हैं और जो ब्योरोक्रेसी है, वह सरकार पर इस कदर हावी है कि अगर उनके खिलाफ संसद सदस्य कोई शिकायत सरकार से करते हैं, तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। यह आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि कोई कार्यवाही उन अधिकारियों के खिलाफ़ नहीं होती है। मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दो सप्ताह से संसद सदस्यों के, मिनिस्टरों के टेलीफोन डिसरप्ट हुए पड़े हैं लेकिन कम्पलैंट करने के बाद भी आपके अधिकारियों की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। नार्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू और एम०पीज के दूसरी जगहों पर टेलीफोन खराब पड़े हैं और वे ठीक नहीं हुए हैं। आपकी जानकारी में यह चीज भी आई होगी कि लोक सभा स्पीकर साहब का टेलीफोन भी परसों खराब हो गया और काफ़ी देर खराब रहा। तब स्पीकर साहब को ध्यान आया कि इस पर कालिंग एटेंशन होना चाहिए। आप यह समझ सकते हैं कि लोक सभा के स्पीकर साहब का टेलीफोन खराब हो जाए और कम्पलैंट करने पर भी काफ़ी देर तक वह सुधरता नहीं, तो इससे खराब स्थिति और क्या हो सकती है।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 101 और 197 को बुकिंग करने के लिए या कम्पलैंड करने के लिए टेलीफोन मिलाते हैं, तो 10-10 मिनट तक आप की टेलीफोन एक्सचेन्ज के कर्मचारी उसको रिसीव करने को तैयार नहीं है। दूसरे यह है कि टेलीफोन मिलाते कहीं हैं और मिल कहीं जाता है। जिस टेलीफोन नंबर पर टेलीफोन मिलाते हैं, बहां पर टेलीफोन मिलने वाला नहीं है। ऐसा रोजमर्रा होता है और पता नहीं मेरे यहां एम० पी० भवन के नाम दिल्ली में रोज सुबह 7 बजे टेलीफोन आ जाता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : You may become the Chief Minister of Madhya Pradesh some time.

श्री जगपाल सिंह : That possibility is not there at all. यह स्थिति टेलीफोनों की दिल्ली के अन्दर है। बारिश की वजह से यह व्यवस्था खराब हो गई, यह आपने बताया है। यह कोई नई बात आप नहीं कह रहे हैं। 1970 से लेकर अभी तक यही आपका जवाब है इस सदन के अन्दर। जब भी बारिश होगी, तभी टेलीफोन सिस्टम आपका खराब हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इतने वर्षों तक का जो आपका तजुर्वा है, उसके आधार पर इसको सुधारने के लिए कोई योजना आपने बनाई है ?

क्या प्लास्टिक से या किसी अन्य अल्ट्रा-

मार्डन तकनीक से उन केबिल को जमीन में दबाने की कोई योजना आपके पास है? पिछले दिनों स्टीफन साहब ने 10-12 करोड़ रुपये की एक योजना शुरू की थी जिसमें प्लास्टिक के कवर में इन केबिल्स को ज़मीन के नीचे दबाया जाना था। लेकिन वह योजना आज तक वी०आई०पी० क्षेत्रों तक में भी नहीं पहुंची है। मैं जानना चाहता हूं कि केबिल्स को ज़मीन के नीचे दबाने की उस योजना को वे कब तक पूरा करेंगे ?

हमारे टेलीफोन हमारे उद्योगों के विकास का बहुत बड़ा साधन हैं। पिछले दो सप्ताहों से दिल्ली, गाजियाबाद, नौएडा में जो हमारे उद्योग हैं, उनको इस टेलीफोन सिस्टम के डिस्टर्ब हो जाने से कितनी हानि हुई होगी, इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। उन उद्योगों की ओर व्यापारियों की पूरी की पूरी सम्पर्क व्यवस्था डिस्टर्ब हो गयी। वे एक दूसरे से सम्पर्क नहीं कर पा रहे हैं। आपने जो टेलीप्रिण्टर्स और टेलेक्स के प्लान्ट सारे देश में लगाये हैं उनके न काम करने से इन उद्योगों को कितना नुकसान हो रहा है।

अब मैं देहातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपकी टेलीफोन व्यवस्था शहरों तक है। अगर आपने सारे देश की एकता को बनाये रखना है तो सारे देश में इस व्यवस्था का विकास कीजिए। हमारे हिन्दुस्तान में 8-9 हजार एक्सचेंज हैं। उनमें से केवल तीन हजार एक्सचेंज ही छोटे-छोटे टाउन्स में, देहातों में नहीं, लग पाये हैं। यह सब 35 साल में हुआ है। इसका कारण भी मैं जानना चाहूंगा कि आप का यह डिस्क्रिमिनेशन देहातों के प्रति क्यों है ?

आपने एक हजार टेलीफोन एक्सचेंज पर इतने कर्मचारी भर्ती किए हैं कि इतने कर्मचारी दुनिया के किसी मुल्क में भर्ती नहीं किए गये हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : वहां इतनी लेबर कहां है ?

श्री जगपाल सिंह : यह स्थिति है। मैं आप से कहना चाहूंगा कि आप देहातों और छोटे कस्बों को और अधिक टेलीफोन एक्सचेंजों से जोड़िये। इसके साथ नार्थ ईस्टर्न एरिया में इस योजना को ज़्यादा से ज़्यादा ले जाने की कोशिश करें।

हमारा जो टेलीफोन का सिस्टम है, हमारे जो टेलीफोन एक्सचेंजों के प्लांट्स हैं, वे हमारी आई० टी० आई० की फैक्ट्रियों में बन रहे हैं। हमारे देश में इन फैक्ट्रियों में बनने वाले प्लांट्स की स्थिति को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे ये प्लांट्स विदेशों में लगते होंगे, जैसे कि कुवैत में लग रहे हैं, अम्मान में लग रहे हैं और दूसरी इस्लामिक कन्ट्रीज में लग रहे हैं, तो वहां भी परेशानी होती होगी। क्योंकि हम अपने देश में ही अपनी टेलीफोन व्यवस्था को सुधार नहीं पाये हैं तो यह सिस्टम उन देशों में भी परेशानी उत्पन्न करता होता। जब आपके पास अच्छी तकनीकी नहीं है, अच्छी व्यवस्था नहीं है तो आप इस्लामिक कन्ट्रीज को भी अच्छी तकनीक नहीं दे पा रहे होंगे। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो प्लांट वहां लग रहे हैं क्या उनकी भी यही हालत है? अगर यही है तो निकट भविष्य में इस सिस्टम में सुधार करने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं जिससे कि हमारे देश की प्रतिष्ठा पर आंच न आने पाये ? जब तक हमारी टेक्नोलोजी अच्छी न हो तब तक विदेशों में जाकर के प्लांट लगाना कहां तक हमारे देश की प्रतिष्ठा के लिए हितकर है ? यह हमारे देश की प्रतिष्ठा का भी सवाल है।

हमारे देश के उद्योगों में हमारी टेलीफोन व्यवस्था और संचार के दूसरे साधनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे उद्योगों का पूरा का पूरा विकास इस पर निर्भर करता है। अपने देश के आर्थिक विकास के लिए हमारे पास अच्छी तकनीक होनी चाहिए और अच्छी टेलीफोन व्यवस्था होनी चाहिए। आपके पास अच्छे टेलीप्रिन्टर होने चाहिए, अच्छे टेलेक्स होने चाहिए।

तभी आप उन्हें अच्छी टेलीफोन व्यवस्था दे पायेंगे। अगर आपकी इन चीज़ों में तकनीक अच्छी नहीं हो पाती है, वह कमज़ोर रहती है तो आप इसकी वजह से इस देश के लोगों को सामाजिक न्याय नहीं दे पायेंगे। देश की अच्छी आर्थिक उन्नति के लिए, देश में लोगों को सामाजिक न्याय देने के लिए आप टेलीफोन की, टेलीप्रिन्टर्स की, टेलेक्स की अच्छी व्यवस्था करें। हमारी आर्थिक उन्नति काफी कुछ इस सिस्टम से जुड़ी हुई है। टेलीफोन डिपार्टमेंट की हिन्दुस्तान में कोई अलग हैसियत नहीं है बल्कि यह सारे देश की उन्नति और सामाजिक न्याय के सवाल के साथ जुड़ा हुआ है।

उन सब सवालों को ध्यान में रखते हुए टेलीफोन के संबंध में एक दीर्घकालीन योजना बनाने के बारे में सरकार विचार कर रही है या नहीं ?

जब रायबरेली में स्टीफन साहब के समय में फैक्ट्री लगाने की बात हो रही थी उस समय यहां पर उन्होंने कहा था कि क्रासवार प्रणाली और स्टाउजर प्रणाली से इलेक्ट्रानिक सिस्टम ज्यादा बेहतर है। उस वक्त यह सरकार की रिपोर्ट थी, आपकी नौकरशाही की रिपोर्ट थी कि जो क्रासबार फैक्ट्री बनाने की योजना रायबरेली में चल रही है वह ज्यादा सफल नहीं होगी। इस फैक्ट्री का ठेका देने के पीछे क्या कारण थे। इलेक्ट्रोनिक प्रणाली के लिए भारत सरकार की निकट भविष्य में क्या योजना है ? सरकार क्रासबार और स्टाउजर प्रणाली की जगह इलेक्ट्रानिक डिजिट की योजना बनाने पर विचार कर रही है या नहीं ? इसमें कितने वर्ष लगेंगे ?

दिल्ली के बारे में एक बात मुख्य रूप से कहना चाहता हूं। दिल्ली के बारे में इन्होंने कहा था कि जितने लोगों ने आवेदनपत्र दे रखे हैं उन सबको कनेक्शन दे दिया जाएगा। लेकिन कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। आवेदनपत्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। टेलीफोन उद्योग कोई घाटे का उद्योग नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार कौन सी योजना बना रही है जिससे देश के प्रत्येक आवेदक को कनेक्शन दिया जा सके ? आज देश में छोटे-बड़े उद्योग धन्धे बढ़ रहे हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में कितने लोगों को टेलीफोन कनेक्शन देने की सरकार की योजना है ? क्या 1990 तक भी सरकार प्रत्येक आवेदक को कनेक्शन दे पाएगी ?

क्या इस तरह की किसी योजना पर विचार किया जा रहा है ? आने वाले समय में इलेक्ट्रानिक सिस्टम की कितनी फैक्ट्रियां लगाने का विचार किया जा रहा है ? प्रत्येक वर्ष 80 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाने की क्या कोई योजना सरकार के पास है ? क्या आप इलेक्ट्रानिक डिजिट योजना पर विचार कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में आवश्यकता को पूरा किया जा सके ? छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने को है और अभी तक आप 28 अरब रुपया भी खर्च नहीं कर पाए हैं। अब छठी पंचवर्षीय योजना के अगले 2-3 सालों के लिए क्या कोई कार्यबद्ध और समयबद्ध प्रोग्राम इस देश को इस उद्योग में इंडिपेंडेंट बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है ?

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Jagpal Singh Ji, so much of time you should not take when you use your telephone !

SHRI V.N. GADGIL : Sir, I must begin by thanking my friend, Mr. Jagpal Singh for this Calling Attention because the Communication Ministry was not discussed and therefore, we had no opportunity to explain our point of view, our difficulties and our problems. Therefore, I am thankful for this opportunity.

I would request the House that before you pass on any judgment on the function-

ing or performance, there are certain facts which require to be stated. In the first place, please try to understand the vastness and the range of the operation.

To-day we have eight lakhs of employees, 25 lakhs of telephone lines, postal services for more than 1,40,000 villages. We have to provide service right from the height of Himalayas to the deserts of Rajasthan. Therefore, it is likely that there are some shortcomings. There are certain defects. When you have such a huge organisation, it is almost inevitable that such shortcomings are there.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri) : Number 199 does not work.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He is coming to that point. Please wait.

SHRI HARISH KUMAR GANGWAR : (Pilibhit) : It does not speak at all.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur) : Once you book a trunk call, you can never cancel it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Sometimes there is over-lapping also.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : यह कालिंग अटेंशन तो जनरल है।

SHRI JAGPAL SINGH : It is vague.

SHRI V.N. GADGIL : When so many hon. Members are prompting at the Calling Attention, I have to stop and listen to them.

Strictly speaking the scope of the Calling Attention is in respect of failure which is a result of rain. But he has raised so many issues. I will try to answer all of them. What are the basic reasons for the shortcomings ? In my three months' experience I have come to certain conclusions. The first is.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : You can say with respect to your previous experience with regard to telephone.

SHRI V.N. GADGIL : That of course, I will say. The first is the financial constraints. We would like to have greater investment. I will presently come to some aspects.

The Calling Attention says : "reported disruption of telephone". Of course, it is recent. The definition of Calling Attention is a matter of urgent and public importance. Therefore, it is something which has occurred recently. I think that is the scope. I am prepared to answer all questions.

The basic reason according to me is the financial constraints that we have. The second is the provision of equipment and space which is not as adequate as it should be. But the most important reason according to me is two-fold.

Historically, we went in for various technologies. To match these technologies with one another is not a very easy job. But more than that, the most fundamental reason according to me is this—there are 3.5 telephones per thousand persons in India compared to 50 per hundred in other countries. For example, in America there are some cities and places where the number of telephones is more than the number of people. What is the result in India ? The result is, the lines are over-loaded. They get congested. The number of calls per line is very high. I am not complaining. Several hon. Members come to me. My colleagues come to me for temporary connections. They are all genuine, because somebody has been suffering from heart attack. Everyday when I leave Lok Sabha, both my pockets are full. There are genuine cases. There are cases of hardship..

SHRI BHOGENDRA JHA (Madhubani) : The cases must be a few.

SHRI V.N. GADGIL : You think it is only one, but ultimately when we give such temporary connections, the lines get overloaded. That is a fact of life. That is not the case—that the cases which hon. Members bring are not genuine. When there are 3.5 telephones per thousand persons, you can imagine the load that exchanges have to take.

That is particularly so in cities like Bombay, Delhi and Calcutta.

The other point which he has specifically asked is about electronic exchanges. We have decided to go in for electronic exchanges. As the hon. Member probably knows, an electronic switch factory is being established at Gonda.

The second factory will also come. We have not taken a decision as to which technology to adopt and the location.

SHRI JAGPAL SINGH : Is it collaboration with France ?

SHRI V.N. GADGIL : The first factory is based on the French technology which is coming at Gonda, an underdeveloped part of the country. Hon. Member wanted to know the extent of change into electronics. As far as Delhi is concerned, Delhi will have 1,35,000 lines electronic exchange in phases by 1985, and about 4 lakh line electronic exchanges are under installation. For example, in Bombay, next month one more exchange will come.

Then again, he mentioned about the waiting list. The present list as it is, and I am very cautious—because the list is going on increasing every day—is expected to be cleared by 1985, this is for Delhi ; I am talking about Delhi. In many other cities also, by a year or two, the existing waiting list is expected to be cleared. But as you are aware and the hon. Member himself has said in view of the importance of communication in the development of industries and general economic development, as more and more industries come up, the demand goes on increasing and the waiting list goes on increasing. What I can say is, the waiting list in Delhi as of today is expected to be cleared by 1985.

Then, he mentioned that in some developed countries, no fault does occur. I do not want to justify by saying what happens in other countries. It is not correct to say that in all the developed countries, the system is very good. For example, take London. London telephone system is pretty bad. The other day, I read an article in the *London Observer* which was more critical of the London telephone system. The article said, "You ring and get a wrong number". The article ends by saying that the London system is so bad that the past tense of "ring" should be "wrong" ! This is the state of affairs in the city of London. We are, after all, an under-developed country.

श्री जगपाल सिंह : लन्दन के 1,000 टेलीफोन पर 8 आदमी कुल होते हैं तब भी डिसरप्ट नहीं होता है।

SHRI V.N. GADGIL : You are right because of certain conditions prevailing there. The number of operators—employees—per thousand line is very much less. And there are conditions which are completely different in this country from what obtains there. In spite of all that, in cities like London, the system is not at all very satisfactory.

There is again another reason, apart from the basic reason that I have said. In some parts of India, there is power shortage and one thing I would request the hon. Members to please bear in mind that the telephone equipment is very sensitive. The failure of air-conditioning or a little bit of dust or even a little more than the permissible heat affects the equipment. Therefore, the fault in the working is two-fold—the fault of the machine as well as human fault.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Why can't you have generators in every exchange ?

SHRI V.N. GADGIL : Sir, some exchanges are in rented buildings and therefore everywhere it is not possible.

What happens in the rainy season ? That also I will request the House to understand. What is the problem ? If a digging operation affects the power line or the water line, the defect is immediately looked into and identified because the supply stops immediately. In the case of cables, supposing the cable is affected by digging or by traffic vibrations during the digging operations, the telephones are not affected immediately. You only come to know that the cable is

affected by digging when rain comes or water comes. And when the rain comes, then the moisture and other factors affect the cable line and then the subscriber does not get his line. Therefore, I mention and Hon. Member also mentioned about that point. The policy decision taken some years back is that ducting should be provided. It is a PVC pipeline and embedded in concrete and, therefore, it is protected from rain. As far as Delhi is concerned, we have so far completed a total of 30%. The cost is about Rs. 5 crores. To give that much protection in monsoon, not only it is costly but it takes time. Another difficulty peculiar to Delhi was that we are not permitted to dig ourselves till 26th January is over. Last year, further difficulty was we had Asiad and NAM. Therefore, no digging could take place on the part of the Telephone Department to correct the defect in cables. Then again another factor is that we have, as Hon. Member mentioned, other methods to operate. For example, we have now advertised "Dial before you dig". If any private party or public undertaking wants to start digging, we request them to first contact us. And what do we do ? For example, in Bombay now, we have got a Coordination Committee consisting of State Government and Municipal Corporation and other public agencies. They sit together and try to take a coordinated action so that digging for water pipes, again digging by some other agencies, may not occur. To put in a different way, one operation is that as long as digging takes place, we pour water. These are technical matters but in layman's terms, you have seen bicycle puncture. How does one detect ? You take out the tube, put it in water. Then the bubble comes out and you detect where the leakage is. Here there is the reverse process. We pour, instead of putting the tube into the water, water over it. And then we detect the air coming out and it is possible to detect the defect and locate it. Imagine how many tankers you have to bring to pour that much water. Therefore, these are some of the difficulties and problems which occur during rainy season. New thing we have started is using of jelly cables. Jelly is like vaseline so that water does not enter. Another method is pressurisation. By this method, it is possible to detect the defect, by putting some air in the cables so that the air comes out and you can detect where the fault lies.

Hon. Members himself has made a reference to fibre glass. This is a modern technology. We have given the assignment. Some fibres are being used. They are under trial and we do not want to go whole hog unless the trials are successful. If the trials are successful, then we will take a policy decision to use this fibre glass for the purpose of cables for all the other exchanges.

These are some of the masures we take. I agree with Hon. Member and that is mentioned in our Plan also, that communication expansion must take place in the rural areas. I do not want to repeat the figures. They have been given earlier in reply to question and also in annual reports. But there is a policy decision that development must now take place in rural areas. The telephone must not remain a luxury article for urban rich. That is what we have decided. It must go to the poor. You have been told in the House earlier that we have to reduce the norms, with regard to revenue. We have reduced as far as the backward and hilly areas are concerned. Some concession is given for development in rural areas.

Therefore, I submit with great humility that we are conscious that for the economic and industrial development of this country, communication with rural areas must expand and the plans are already there.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You mention something about Rae Bareilly exchange. He was very particular.

SHRI HARISH KUMAR GANGWAR : Something should be stated about wrong number.

SHRI V.N. GADGIL : As far as Rae Bareilly cross-bar is concerned, once we have decided to go in for electronics, it is not possible to just throw out cross-bar. About strowger, we have already decided to do away with it. It is 25 years old and its life is almost over particularly in Calcutta.

Similarly, with regard to cross-bar, it will

be phased out gradually. It will not be possible in one go.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Mangal Ram Premi—he is not there.

Shri B.D. Singh.

श्री जगपाल सिंह : उपाध्यक्ष जी, टेलीफोन एक्सचेंज के कर्मचारी जो हैं वे स्पेशली वी० आई० पीज के साथ ऐसा करते हैं कि टेलीफोन तो किसी दूसरे ने किया, लेकिन उनके खाते में उसको जोड़ देते हैं। मैं समझता हूं मेरे अलावा अन्य संसदसदस्यों के साथ भी ऐसा हुआ है और मिनिस्टर्स के साथ भी यही होता होगा कि टेलीफोन तो करे कोई और जोड़ दिया उनके खाते में। कोई व्यापारी या बिज़नेसमैन टेलीफोन करेगा, जिसके यहां से मंथली बंधा हुआ है, तो उसकी कालस को वी० आई० पीज़ के खाते हैं जोड़ दिया जायेगा। मैं खुद कम्पलैंट दे रहा हूं कि सहारनपुर एक्सचेंज से दो बार डिफरेन्ट स्टैटिस्टिक्स दी जा चुकी हैं। यह बिलकुल गलत है।

MR. DEPUTY-SPEAKER. If they book it in the name of the VIP, then immediately the telephone exchange can again contact him and check up whether it is actually booked by Mr. Jagpal Singh. They can have a reference. That can be done and that can be verified.

SHRI V.N. GADGIL : The complaint the hon. Member has made I will certainly verify. I also accept that there are black-sheep in some of the employees. I do not deny. But the difficulty is : I tell you what it is, because I myself went into the question. Take the linesman. He mixes the lines. Now Now it is very difficult to locate. Supposing you catch, you cannot have a 24 hour-watch over him. Even if you put a watch and even if he is caught in the act of doing the mischief, he will say, 'It is already there and I am only trying to repair.' We have tried to see from various points of view. I have myself given an assignment to our technical officers—'Use all your technical ingenuity and find out a mechanical devise eliminating the human element so that the linesman cannot commit any mischief.' They are doing that exercise whether it is possible.

Secondly, we have observers to find out what mischief is being done and who is doing that. My hon. friend will agree that I would not like to disclose what is being done. If it is disclosed, the operator will know and therefore, we will not be able to defect it.

श्री बी० डी० सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, टेलीफोन व्यवस्था लगातार अस्त-व्यस्त चली आ रही है और इस विषय में इस सदन में भी समय समय पर चिन्ता व्यक्त की गई है। हमको बड़ी आशा बंधी थी कि गाडगिल साहब ने इस मंत्रालय का भार सम्भाला है इसलिए इसकी व्यवस्था सुधरेगी और अभी हमने वह आशा छोड़ी भी नहीं है, हम अब भी उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से वे रुचि ले रहे हैं, उससे व्यवस्था में सुधार होने की सम्भावना है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : You must give him some more time. It is only three months since he took charge. But he is a capable Minister.

श्री बी० डी० सिंह : आज टेलीफोन व्यवस्था की बुकिंग की हालत यह है, जैसा कि मेरे पूर्ववक्ता ने भी कहा है, आप 177, 199 या 180 को डायल कीजिए तो रिंग होती रहती है परंतु उठाने वाला कोई नहीं होता। या तो सुपर्विजन की कमी है या फिर पता नहीं क्या बात है। मैं समझता हूं यदि समर्पित भावना से लोग काम करें तो सुधार हो सकता है। एशियाड के समय में बड़ी अच्छी व्यवस्था चली थी और उस समय हमें कोई शिकायत नहीं थी। अब भी काम करने वाले वही लोग हैं लेकिन वह स्पिरिट नहीं रह गई है। इसमें सुधार हो सकता है, यदि इस पर अधिक ध्यान दिया जाए।

अभी हमारे साथी ने बिलिंग की समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया कि बिल

ज्यादा आ जाते हैं। रिपोर्ट करने पर यदि बिल ज्यादा है तो उसको घटाकर कम कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कैसे हो जाता है? इसके खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिए। मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या मीटरिंग की व्यवस्था कन्ज्यूमार-एन्ड पर नहीं हो सकती है? क्या मीटरिंग की व्यवस्था कन्ज्यूमर-एन्ड पर करने में ज्यादा कॉस्ट आती है? यदि नहीं आती है, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? आम पब्लिक के लिए जो पब्लिक फोन्स हैं, वे एक परसेंट से कुछ ही ज्यादा ही होंगे। इसमें मेरा खुद का अनुभव है कि इनमें पांच से दस परसेंट ही काम करते होंगे। ये फोन्स हास्पिटल और स्टेशन पर होते हैं, जो कि अक्सर खराब रहते हैं। इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इनकी वर्किंग को भी सुधारना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन की व्यवस्था के बारे में आपने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि वह व्यवस्था ठीक हो। मैं आपको इलाहाबाद के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे सब-डिवीजन हैडक्वार्टर के लिए ट्रंक-कॉल बुक कराने में डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से सम्पर्क स्थापित नहीं हो पाता है। 15-20 किलोमीटर होने पर भी सम्पर्क स्थापित नहीं हो पाता है जबकि पूरा दिन बीत जाता है। इसलिए इस व्यवस्था को भी ठीक करने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए।

एक बात मैं आपके विभाग के टैक्नीशियन्स और इन्जीनियर्स के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जो विदेशों में काम करते हैं, उनकी रिपोर्ट अच्छी है कि वे अच्छा काम कर रहे हैं। बाहर काम अच्छा हो रहा है, लेकिन हमारे यहां काम अच्छा नहीं हो पाता है। इसका क्या कारण है? आपने फैसला लिया है और आप फ्रैंच टैक्नालाजी पर आधारित गोंडा में एक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित कर रहे हैं।

अभी कुछ दिनों पहले, जैसा कि अखबारों में पढ़ा था, कोई इंग्लैंड की कमेटी और जर्मन की कमेटी यहां आई थी। इसमें कुछ इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी। जिसके अन्तर्गत पांच लाख प्वाइंट्स होंगे। इस सम्बन्ध में क्यों फैसला नहीं हो पा रहा है? आपने किस टैक्नॉलाजी को एप्रूव किया है और आप इसे कब तक लगाना चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, टेलीफोन विभाग की कार्य प्रणाली में अध्ययन के लिए एक सरीन कमेटी का गठन हुआ था। जिसकी रिपोर्ट एक साल पहले सम्मिट हो चुकी है। इस कमेटी में सारे एक्सपर्ट लोग थे। इस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण संस्तुतियां हैं। जिसमें यह सिफारिश की गई है कि पोस्ट और टैली काम्यूनिकेशन दोनों का अलग-अलग विभाग होना चाहिए। पिछले साल पोस्टल विभाग में 110 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है जिसका भार टेलीफोन विभाग पर पड़ता है। व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल रही है। इस समय टेलीफोन विभाग में 99 कैडर्स के लोग काम कर रहे हैं।

जैसा हमारे साथी ने भी कहा है—100 टेलीफोन्ज़ पर करीब 10 लोग लगे हुए हैं। यह संख्या बहुत ज्यादा है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि इन को घटाकर तीन कैडर्ज़ बनाये जा सकते हैं और जो ज्यादा लोग लगे हुए हैं उनकी संस्था को कम किया जा सकता है। सरीन कमेटी की यह जो रिकममैण्डेशन है तथा जो अन्य रिकमैन्डेशन्ज़ हैं उनके बारे में सरकार कब तक फैसला करेगी। आप से पहले स्टीफन साहब आप के डिपार्टमेन्ट के मिनिस्टर थे, उनकी भी यह मान्यता थी कि सरीन कमेटी ने जो डायग्नोसिस की थी, करीब-करीब आपके मंत्रालय की भी वही डायग्नोसिस हैं इसलिए इस संबंध में आप कब तक निर्णय लेने जा रहे हैं?

13 hrs.

दिल्ली में वर्षा होने के कारण जो टेलीफोन व्यवस्था अस्तव्यस्त हुई है—इसका एक कारण यह भी है कि हमारे यहां जो केबिल्स लगे हुए हैं,

उनकी लाइफ़ 25-30 साल होती है, लेकिन वे 50-60 साल से चलते आ रहे हैं। वे बहुत पुराने हो चुके हैं, पहले से ही वे डेमेण्ड हैं, बारिश होने से पानी उनके अन्दर चला जाता है, जिससे शार्ट-शर्किट हो जाता है। इनको सुधारने तथा रिप्लेस करने के लिए सरकार कब तक व्यवस्था करेगी ?

SHRI V.N. GADGIL : Sir, I will take the last point first. As far as the cables are concerned, the problem is like this. Newer lines are given and you want more cables. On the other hand cables are there whose life is over and we have to replace them. Therefore, we have to find a via-media where both can be satisfied. For example, in Calcutta some cable lines are 50 years old. So, urgency in that area is that replacement should take place.

As far as the Sarin Committee is concerned, I am giving rough figures that the Sarin Committee made about 337 recommendations, out of which we have accepted and implemented more than 200 recommendations. We did not agree to about 30 recommendations and about 58 recommendations are under process because with regard to those recommendations other Ministries are concerned. So, in regard to them inter-ministerial discussions are being held.

With regard to the point raised about the wrong bills, I would submit that this point has been raised in the House several times. Sir, we have a method by which it can be found out roughly-speaking as to what is the extent of wrong billing. If I remember the figure rightly, during 1981-82 a rebate to the extent of about Rs. 1/- crore was given by the Department where it was satisfied that the Bills were wrong.

Sir, the Hon. Member has mentioned about the large number of employees in the Department. Sir, it is a two-fold question. On the one hand we require that the number of employees should be reduced. Then the question is whether there should be a retrenchment or the effort should be made to absorb them.

Sir, the Hon. Member has asked whether the Meters can be located at the Subscriber's house. Sir, my difficulty is that I have no science background at all. So I don't know much of its technical feasibility. Fortunately the Hon. Member is an M.S.C. But what I have been advised by the experts is that it is not possible to locate it at the subscribers' house. Nowhere in the world meters are located at the subscriber's house. That is not technically feasible.

With regard to the PCOs, where they are not working properly, we have taken action to discontinue them.

Sir, we have recently adopted a policy to give PCOs to the handicapped. Personally I am satisfied with their working. I have seen cases where lame persons, or deformed persons, who have no hope in life, they are given PCOs and out of fifty paise he gets twenty paise ; and on an average he gets Rs. 300 per month. So, one life is at least saved. I am satisfied with this policy. Our experience is that the handicapped persons do not normally indulge in any kind of mischief.

Then, Sir, the last point he made is about the Operators. There I would like the cooperation of everyone, including the MPs. It is true that some operators—not much in percentage, but a small percentage is there—are rude and uncooperative. If such a thing is brought to our notice, we take action.

Last week, my colleague gave the figures as far as Delhi was concerned—how many we suspended and how many we dismissed. Here, I must frankly state one difficulty : if such an Operator is suspended because one MP complains that he or she was rude, then somebody else comes to us and says : 'Withdraw that suspension order' ; or some Union comes and threatens a strike. That is the parameter within which I have to work. And each case we decide on merits.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Sometimes, the same MP also requests you not to take action.

SHRI V.N. GADGIL : So, I would seek

the cooperation of every hon. Member. When we take strong action, we want your support. Otherwise, such black elements cannot be weeded out.

MR. DEPUTY SPEAKER : With regard to these employees in the Postal Department, as one who was in the Postal Department, I may state that the actual number of regular departmental employees is only 3-1/2 lakhs. The extra-departmental staff number more than 3-1/2 lakhs. These figures you gave. Therefore, the number of regular employees is only 3-1/2 lakhs, not 7 lakhs.

SHRI HARISH KUMAR GANGWAR : Sir, your name is not in the Calling Attention motion.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, आधुनिक समाज में जैसा कि मंत्री जी ने स्वीकार किया है टेलीफोन शोक के लिए नहीं लगाया जा रहा है बल्कि टेलीफोन नागरिक जीवन और नागरिक प्रशासन, वाणिज्य आदि बुनियादी आवश्यकताओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इस हाउस में कई बार टेलीफोन के बारे में चर्चा हुई है। कई बार कालिंग एटेंशन भी हुए और मंत्रियों ने जवाब भी दिये।

मान्यवर, आज भी एक जवाब दिया गया है और हमें आश्चर्य होता है इस जवाब को देखकर कि ढाई घंटे लगातार वर्षा होती रही और इस कारण सारी टेलीफोन व्यवस्था गड़बड़ हो गई। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ ले जाऊंगा, मैं इसका जवाब नहीं चाहता कि यह हिन्दुस्तान रेगिस्तान नहीं है, यहां पर बरसात आज पहली बार नहीं हुई या एक ही बार नहीं हुई बल्कि बरसात अनेकों बार हुई है और ढाई घंटे तो क्या बल्कि एक-एक दिन, दो-दो दिन तक बरसात होती रही और दिल्ली में बसों के ऊपर तक पानी आ गया था और उसके बावजूद भी इतनी बुरी तरह से टेलीफोन खराब नहीं हुए जितनी कि पिछली बरसात में टेलीफोन खराब हुए। मान्यवर, यह कह देने से कि बरसात की वजह से टेलीफोन खराब हो गये, बात पूरी नहीं बनती। यह बड़े खेद की बात है कि हिन्दुस्तान में जैसा कि हमारे पूर्व साथियों ने बताया कि टेलीफोन बहुत कम हैं। हमारे यहां टेलीफोन की संख्या 1000 व्यक्तियों पर 47 है जबकि टोकियो में 1000 आदमियों पर 607 है, स्टाकहोम में 756 है, न्यूयार्क में 810 है। यह आश्चर्य की बात ही है कि हिन्दुस्तान में 1000 आदमियों पर केवल 47 आदमियों के यहां ही टेलीफोन हैं। फिर भी हमारे यहां टेलीफोन बेकार रहते हैं। अभी बातचीत चल रही थी कि भारत में 1000 टेलीफोनों पर 110 कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए और टेलीफोन की सुविधाओं को देखने के लिए एक भारी फौज है। स्वीडन में 1000 टेलीफोनों पर 8 आदमी काम कर रहे हैं, नीदरलैंड में 12 काम कर रहे हैं, जापान में 10 काम कर रहे हैं और इंग्लैंड में 11 काम कर रहे हैं। इस तरह से वहां पर 8 से लेकर 12 आदमी काम करते हैं और वहां 3 या 4 टेलीफोन खराब होते हैं और हमारे यहां इस के मुकाबले में 110 आदमी काम करते हैं और मैं समझता हूं कि यहां पर 100 टेलीफोन इस एक हजार में से अक्सर बेकार ही रहते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यह कैसे होता है। मैं यह नहीं कहता कि कर्मचारी कम किए जायें। हमारे यहां मजदूरी की प्राब्लम है और दूसरी अनेक समस्यायें हैं। हमको इसमें कोई परेशानी नहीं है कि 1000 टेलीफोनों पर 110 आदमी क्यों काम कर रहे हैं। मैं तो यह चाहता हूं कि यह विभाग और हमारी सरकार इन 110 कर्मचारियों को इतने अच्छे ढंग से ट्रेन्ड करे, या ऐसे औजार दे, या इस प्रकार की तकनीक का विकास करें जिससे कि हमारे यहां टेलीफोन बिगड़ें नहीं। हमारे यहां जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको कम करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि दूसरे देशों से हमारी अलग समस्या है।

मान्यवर, मैं यह प्राय: देख रहा हूं। आज यह कालिंग अटेंशन, जैसा कि हमारे मित्र ने भी कहा, मंजूर नहीं हुआ होता यदि स्वयं स्पीकर

साहब का और स्वयं मंत्री जी का टेलीफोन खराब न हुआ होता। इसके अतिरिक्त यह भी एक बड़ी समस्या है कि अगर हम स्पीकर साहब के यहां टेलीफोन करते हैं तो उधर से किसी सरदार जी की बीवी की आवाज सुनाई देती है। अगर हम डिप्टी स्पीकर को टेलीफोन मिलाते हैं तो कभी कभी ऐसी ऐसी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिनका वर्णन यहां उचित नहीं होगा। उधर से आवाज आती है कि मैं फलां बोल रहा हूं, आप कौन साहब बोल रहे हैं। कभी-कभी तो बड़ी बड़ी हास्यास्पद बातें सुनने में आती हैं और कभी कभी अशोभनीय बातें भी सुनने को मिलती हैं। हमने एक दफा डिप्टी स्पीकर साहब के यहां टेलीफोन मिलाया तो बड़े बड़े विशेषण जोड़े जा रहे थे। पता नहीं लग रहा था कि वे डिप्टी स्पीकर साहब के यहां से जोड़े जा रहे थे या कहीं और से किसी जाहिल आदमी के यहां से जोड़े जा रहे हैं।

आपके 199, 198, 197, 184 नम्बर, टेलीफोन अपने हैं, सरकारी हैं। उन टेलीफोन नम्बरों पर काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में हमने देखा है कि एक-एक, दो-दो मिनट, पांच-दस मिनट तक उन पर घंटी बजती रहती है लेकिन टेलीफोन नहीं उठाया जाता है। स्वाभाविक रूप से टेलीफोन करने वाला आदमी झल्ला उठता है। उनसे पूछा जाता है कि आपने इतनी देर टेलीफोन उठाने में क्यों लगायी तो कहा जाता है कि इसके बारे में बताने का डिपार्टमेंट से आर्डर नहीं है। हमने इसके बारे में संचार मंत्री को लिख कर दिया था। अगर आप उन कर्मचारियों को कुछ कहियेगा तो गाली सुन लीजिए या विशेषण सुन लीजिए।

मैंने वाराणसी में 70-80 कम्पलेंट्स की हैं लेकिन आज तक एक भी कम्पलेंट पर न तो कोई कार्यवाही हुई और न कोई जांच हुई। मेरा खुद का टेलीफोन खराब रहता है। हम विपक्ष के सदस्य हैं। जब हमने मंत्री जी से मुलाकात की तो वे हम से बड़े प्यार से और आदर से मिले। सब कुछ बात उन्होंने हमारी सुनी। मगर मान्यवर कर्मचारियों के दिमाग में यह बात बिठा दी गई है कि यह आदमी विपक्ष का है, यह सत्तापक्ष का है। इस तरह से कर्मचारी ठीक ढंग से मामले को अटेण्ड नहीं करता। हम कम्पलेंट करते हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती। आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा। हम यह नहीं कहते कि सरकार इस प्रकार का व्यवहार करती है लेकिन अगर कोई कर्मचारी भी ऐसा व्यवहार करता है तो माननीय मन्त्री जी को उस ओर ध्यान देना चाहिए।

हमारे भूतपूर्व संचार मन्त्री श्री स्टीफन साहब थे। मुझे उनके बारे में यह कहते हुए अफसोस होता है कि उन्होंने एक वक्तव्य दिया जो कि 19 जून, 1982 के अखबार में निकला। उसमें उन्होंने कहा कि जो उपभोक्ता असन्तुष्ट हैं वे अपने टेलीफोन को कटवा दें, वापस कर दें। (**व्यवधान**) मैं आपको ऐसे लोगों में नहीं समझता। आप भी उनमें से न हो जाएं, जैसा कि आज आप ने कह दिया कि बरसात के कारण टेलीफोन खराब हो गए। स्टीफन साहब ने कहा कि टेलीफोन कटवा दिये जाएं। उन्होंने एक दूसरा सेन्टेशमी मेरे एक सवाल के जवाब में कहा था कि मेरे पास ऐसी कोई गारन्टी नहीं है कि आपका टेलीफोन ठीक होगा या रहेगा ही। हमारी समझ में नहीं आता कि हिन्दुस्तान का एक मन्त्री ऐसे शब्द कह सकता है। अगर कोई कर्मचारी ये शब्द कहे तो बात समझ में आ सकती है। अब मन्त्री यह सब कहता है तो कर्मचारी जरूर कहता होगा कि ये तो सब ऐसे ही हैं।

अब मैं टेलीफोन कनेक्शन की आवश्यकता पर आता हूं। 1981 में 6 लाख 75 हजार टेलीफोन्स की आवश्यकता थी और पूर्ति 3 लाख 67 हजार थी। 1983 में इस आवश्यकता की संख्या बढ़कर 9 लाख हो गई। 1990 तक डिमांड एक करोड़ 2 लाख 82 हजार हो जाएगी और केवल 53 लाख 32 हजार लाइनें ही दी जा

सकेंगी। यह रिपोर्ट आपके विभाग की है। यह जो मांग और पूर्ति में गहरी खाई बनती जा रही है, इस 49 लाख के अन्तर को कम करने के लिए सरकार के पास क्या योजना है? इस बारे में मैं विस्तार से जानना चाहता हूं।

अभी हाल ही में माननीय योगेन्द्र मकवाना जी ने इस सदन में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 1985 तक हम टेलीफोन सेवाओं को पूरा कर लेंगे। मकवाना जी ने कहा था कि 80 प्रतिशत मांग पूरी कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि रायबरेली और बंगलौर में 5-5 लाख लाइनों की क्षमता वाली फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। यह भी कहा गया था कि टेलीग्राम के संप्रेषण में जो विलम्ब होता है इस बारे में भी ध्यान दिया जा रहा है। इन दो फैक्ट्रियों की स्थापना से समस्या हल हो जाएगी। 144 नए टेलीफोन केन्द्रों का भी आश्वासन दिया गया था और कहा गया था कि इनके जरिए 2 लाख 44 हजार 8 सौ नई लाइनें दी जाएंगी। दिल्ली के बारे में कहा गया था कि इलैक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्र की स्थापना की जाएगी और 12 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से एक अलग इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज बनाया जाएगा। 16 इलेक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित कर 78 हजार नई लाइनें देने की बात कही गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि मकवाना साहब ने जो वक्तव्य दिया था उसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है। क्या आप अपने लक्ष्य को 1985 तक पूरा करने जा रहे हैं? अगर नहीं तो इसमें क्या कठिनाइयां हैं और सरकार इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कर रही है? कहीं यह मात्र आश्वासन तो नहीं रह जाएगा।

सरीन कमेटी की बात यहां पर उठाई गई। सरीन कमेटी के सुझावों के बारे में मन्त्री महोदय ने बताया है कि कुछ सुझावों को अमल में लाया गया है और कुछ को नहीं लाया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन 30-32 सुझावों को अमल में नहीं लाया गया है उनको अमल में लाने में क्या दिक्कतें थीं? क्या आगे चलकर उन कठिनाइयों को दूर किया जाएगा? क्या 1990 तक इन सुझावों को स्वीकार कर लिया जाएगा?

देश में टेलीफोन सेवा के आधुनिकीकरण के लिए और टेलीफोन सेवा को दक्षतापूर्ण बनाने के लिए, इसको विश्वसनीय बनाने के लिए आपने विगत दो वर्षों में क्या किया है? इस बारे में आप आगे क्या करने जा रहे हैं? इन बातों की पूरी जानकारी आप हमको दें।

रायबरेली में देश की सबसे बड़ी इन्डस्ट्री इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज है। हमारी प्रधान मन्त्री जी का वह क्षेत्र भी रह चुका है। वहां पर पांच हजार कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें दो सौ महिलायें भी हैं। यह बहुत बड़ा केन्द्र है। इसने देश को बहुत कुछ दिया भी है। ऐसा देखने में आ रहा है कि टेलीफोन का उच्च-स्तर का विभाग हो या इन्डस्ट्री हो, इनमें भ्रष्टाचार बहुत बढ़ता जा रहा है। एक-दो उदाहरण आपको अभी देता हूं। सबसे पहले, आपसे यह जानना चाहूंगा कि इस प्रकार के भ्रष्टाचारों पर नियंत्रण करने के लिए कौन-सी प्रणाली आप अपना रहे हैं और अब तक इसको दूर करने में आपने क्या-क्या कदम उठाए हैं तथा कितने लोगों को अब तक सस्पेंड किया गया है?

अभी हाल ही में आई०टी०आई० रायबरेली में इन्टक वालों से झगड़ा हुआ था। इन्टक के कुछ कर्मचारी इस टेलीफोन इन्डस्ट्री में घुस गए। यह बात मन्त्री जी को अच्छी तरह से मालूम है। यह बात हाउस में कई बार उठाने की कोशिश की गई लेकिन किसी वजह से यह नहीं उठ पाई। वहां पर पुलिस भी किसी वजह से घुस गई और उसने अन्धा-धुन्ध लाठी-चार्ज किया। मालूम हो रहा था कि यह सीमा का युद्ध-स्थल है। वहां मोटरों आदि में आग लगाई गई, भगदड़ मच गई और मामला इतना तूफान सा हो गया जिसमें काफी लोग पकड़े गए। गोली चलायी गई और

दो आदमी मारे गए। वहां पर यह कहा जाता है कि आठ आदमी भाग गए। ज्यादातर लोगों का यह कहना है कि ये आठ आदमी जान से मर गए हैं और पुलिसवालों ने इनकी लाशों को गायब कर दिया। इतनी बड़ी घटना होने पर यहां से उच्च-स्तरीय नेता लोग भी गए। वहां पर जाकर पालिटिकल मामला बन गया, मैं इससे इन्कार नहीं करता। वहां पर बीस कर्मचारी मुअत्तिल किए गए हैं, वे निर्दोष हैं। मुअत्तिल करने का कारण यह था कि उन्होंने जोर-जोर से कहना शुरू कर दिया कि साहब, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है। वहां के जी० एम० साहब ने कहा कि, आप इस बात को न कहें। लेकिन, उन्होंने कहा कि हम कहेंगें। पब्लिक मीटिंग हुई और न जाने क्या-क्या हुआ ? अन्त में उन बीस कर्मचारियों को मुअत्तिल कर दिया गया जो कि बेगुनाह हैं। उनको चार-चार और पांच-पांच दिन तक जेल में रखा गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह घटना आपको मालूम है या नहीं ? अगर मालूम है तो वहां के एक ईमानदार आफिसर श्री ए० के० श्रीवास्तव जो इन्जीनियर हैं, बार-बार कह रहे थे कि इस घटना में कर्मचारियों की नहीं बल्कि पुलिस की गलती है। उनको क्यों हटाया गया ? वहां के जी०एम०, श्री वाइ०एन० तिवारी को अभी तक रोक रखा गया है। यह बड़े शर्म की बात है। क्यों इस भयंकर दुर्घटना के बाद श्री तिवारी वहां पड़े हैं ?

कानपुर में केन्द्रीय जांच अन्वेषण ब्यूरो ने 11 फरवरी 1982 को छापा मारा। छह व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और मालूम हुआ कि वहां पर पांच करोड़ रुपये का घोटाला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब केन्द्रीय जांच अन्वेषण ब्यूरो के लोगों ने वहां पर छापा मारा और पांच करोड़ का घोटाला पकड़ा और अखबारों ने लम्बे-चौड़े रूप में छापा उस पर आपने क्या किया ? आप घंटी मत बजाइए। अभी सिर्फ आठ मिनट हुए हैं कम से कम तीन मिनट और हैं।···—(**व्यवधान**)

टेलीफोन के बिल के बारे में बातचीत चल रही थी। यह वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है। यह निश्चित है कि मैंने 1982 की जुलाई-अगस्त-सितम्बर में कभी भी ट्रंक-कॉल बुक नहीं किया था। 1982 के जुलाई-अगस्त और सितंबर का मेरा बिल उठाकर देखा जाए तो मेरे पास 1300-1400 रुपए का बिल आया। मैं आश्चर्य-चकित रह गया कि यह कहां से हुआ। टेलीफोन नम्बर भी सही था। मैं यह नहीं समझ पाया कि यह कौन-सी तकनीक है ? यह बड़ा गम्भीर मामला है। आप इस पर ध्यान दें।

और इसी संदर्भ में एक जगह हमने पढ़ा था 34 करोड़ रु० देश भर में टेलीफोन का बकाया है। यह बकाया आपका पूंजीपतियों और बड़े उद्योगपतियों पर है। और यह भी कहा गया था कि 9 करोड़ रु० अकेले दिल्ली के लोगों पर बकाया है। मैं जानना चाहता हूं कि जो यह बकाया है इनमें कितने लोगों के कनेक्शन काटे गए ? या वसूल करने की कोई व्यवस्था आपने की है ? छोटे व्यापारियों का टेलीफोन तो काट दिया जाता है, लेकिन महानुभावों का, पूंजीपतियों का टेलीफोन कभी कटेगा ही नहीं।

टेलीफोन की काल का चार्ज बहुत महंगा है। क्या आप इसको सस्ता करने की व्यवस्था कर रहे हैं ? इस समय शायद 50 पैसे प्रति काल है। क्या आप इसको 30 या 40 पैसा प्रति काल करने के लिए तैयार हैं ?

उपाध्यक्ष जी, मैं गाजीपुर, जौनपुर से चुन कर आया हूं, यह बड़ा देहाती इलाका है और मुझे यहां आये करीब साढ़े 3 साल हो गये, आश्चर्य की बात है कि मैं अपनी कांस्टीट्यूऐंसी गाजीपुर से अथवा जौनपुर से टेलीफोन से कभी बात नहीं कर सका। अन्य शहरों में आपके एस० डी० ओ० टेलीफोन्स हैं, वहां यह भी पोस्ट नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है ? और क्या आप इस क्षेत्र को भी देश

के दूसरे भागों से एस० टी० डी० द्वारा जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं ? ठीक यही हालत बस्ती की है।

SHRI V.N. GADGIL : Sir, the hon. Member has raised a large number of points but I will try to answer all of them. Since he has quoted some figures of Sweden and other countries, I must also point out that when this country became independent, there were only 80,000 lines in this country and today we have 25 lakh.

With regard to the rain, he said it is something which happens every year. That is not quite correct because according to newspaper reports themselves, the rains in Delhi this year were unprecedented both in extent and in intensity and he himself is a journalist. So, I have to accept from the newspaper reports that this year's rain was an all time record.... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Actually after seeing the rain I was envying why the rain is only in Delhi and why not in Madras.

SHRI V.N. GADGIL : It should have rained there.

Now, with regard to the apparatus I have already answered. He made a point about training. We are also trying to give them training both ways—technical training as well as training in behavioural science so that their attitude and approach should improve.

He made a mention of the fact that he belongs to the Opposition. As far as I am concerned, all M.Ps. are equal to me in these matters.

श्री जगपाल सिंह : हमने आपको नहीं कहा। आपके कर्मचारियों के लिए हमने कहा।

श्री वी० एन० गाडगिल : नहीं, आपने नहीं कहा।

I do not say that. The officers also understand the Minister making statement that he does not discriminate between the M.Ps., all M.Ps. are equal...

SHRI HARISH KUMAR GANGWAR : But you will have to convey to your staff also.

SHRI V.N. GADGIL : This message goes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He is Communications Minister, it has automatically gone.

SHRI HARISH KUMAR GANGWAR : Here you are.

SHRI V.N. GADGIL : Then, he has mentioned a point about Sarin Committee that why about 58 recommendations were not accepted. It is not possible for me to go in each and every recommendation but by way of illustration I will mention that the Committee has recommended import of telephone instruments.

We did not think it possible to accept when we ourselves are starting factories for manufacturing of instruments.

Then he posed a question as to whether we will be able to meet the demand. I said on the basis of what my predecessor said that we will try to clear it by 1985, but the answer was always qualified by two things, the finances and the equipment available. I regard it as an indication of the development that demand should exceed the supply and therefore, even if we are not in a position to supply 100 per cent, we will try with various methods that we have adopted.

On the point about the bills I have already answered. A number of steps are taken. I will narrate one by way of illustration. If somebody is a defaulter and if he wants his line to be re-connected, we insist on an advance deposit so that he will not again default.

With regard to Rai-Barcilly, I do not wish to go into details, but very briefly what happened was, in the city itself—not in the factory—three ladies were caught and the allegation was that they had committed a theft. Two of them happened to be relations of one of the ITI employees and therefore, the procession and morcha and all the rest followed. We did not come in because it

was not a dispute between the management and the lower rungs. It was a private dispute taken up by the police and the police are seized with it ; it is for the State Government to decide what is to be done in the matter.

SHRI HARIKESH BAHADUR : But you have to protect your employees because 8 are missing, as he has told.

(*Interruptions*)

SHRI V.N. GADGIL : If you go and enquire, you will find how much protection we have given in the matter of obtaining bail and other things.

With regard to telegrams.....

श्री रामावतार शास्त्री : टेलीग्राम तो पहुंचते ही नहीं हैं।

SHRI V.N. GADGIL : As far as telegram is concerned for improving the system, modernisation by automation of telegram traffic handling has been initiated already and a national network is planned. Then there is a recent facility. I would request hon. Members to visit some time the Eastern Court. It is a very interesting thing to see, it is in the Eastern Court. A new equipment is brought which is called 'Store and Forward System'. A telegram that is given is stored so that if there is a traffic jam, subsequently it is gradually released and quicker transmission is possible. There is also a new equipment which transmits a photograph put here and it is reproduced, say, in Trivandrum. At the time of NAM, I am happy to inform you, not only our performance was good, but the Special Correspondent of *Malayala Manorama* came and congratulated me for the quick transmission of photographs from Delhi to Trivandrum. So, time in transmission is also reduced ; newer and newer technologies are brought in order to improve the system.

SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI : What about Ghazipur ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : इनकी बात करा दीजिये गाजीपुर से।

SHRI V.N. GADGIL : With regard to Kanpur, I understand the inquiry is on.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now Mr. Jaipal Singh Kashyap. I think your work has become very easy.

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, टेलीफोन की हालत यह है कि अगर 3 बार बात कर ली जाये तो चौथी बार टेलीफोन डैड हो जाता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Your complaints will continue as long as the telephone system exists.

श्री जयपाल सिंह कश्यप : हमारे संचार मंत्रालय में तो एक अजीब सी परम्परा रही है। अभी माननीय शास्त्री जी ने कहा और मंत्री जी ने कहा कि उसका कोई वास्ता नहीं है। श्री स्टीफन मन्त्री थे, उन्होंने राय दी थी कि टेलीफोन काम नहीं करता तो उसको कटवा दीजिए, और हमारे पास वापिस कर दीजिए। वह खुद कट गये और चले गये।

अब टेलीफोन्स की एक ही डैफीनिशन रह गई है — उठाओ तो डैड है, आउट ऑफ आर्डर है। अगर मिल गया तो रांग नम्बर और अगर कुछ देर तक बात करते रहे तो उधर से नो रैस्पौंस, उधर से आवाज ही नहीं आ रही है।

और उसके बाद रांग नम्बर और रांग बिल। गाडगिल साहब, आप जैसे मन्त्री के होते हुए इस टेलीफोन डिपार्टमेन्ट की गुडविल बिगड़ती जा रही है। आप अच्छे मन्त्री हैं लेकिन डिपार्टमेन्ट की गुडविल बिगड़ रही है, गाडविल पर डिपार्टमेन्ट चल रहा है। टेलीफोन की हालत यह है कि मेरे यहां बिजली चली गई, मैंने टेलीफोन मिलाया तो मिल गया पार्लमेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन। मैंने कहा, मैं समझ रहा था कि सही जगह मिला है, बिजली चली गई है तो उन्होंने कह दिया एफ० आई० आर० लिखाओ, आपने परेशान किया होगा इसलिए चली

गई। (व्यवधान) इसी तरह से टेलीफोन पाने के लिए बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। बदायूं एक डिस्ट्रिक्ट सेन्टर है। भूमि संरक्षण अधिकारी के कार्यालय के लिए, जो कि एक सरकारी दफ्तर है, उसको शिफ्ट हुए डेढ़ साल से ज्यादा हो गया, मुझ से भी उन्होंने कहा कि जल्दी टेलीफोन लगाने के लिए कह दीजिए, लेकिन उस गवर्नमेंट आफीसर को भी टेलीफोन नहीं मिला। यहां पर दिल्ली में अपने आफिस के लिए टेलीफोन लगाने के लिए पैसा भी जमा करवा दिया लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह नहीं मिला। हालांकि उससे पहले बहुत से लोगों को टेलीफोन मिल चुके हैं लेकिन एक एम० पी० होते हुए भी चूंकि मैं वह तरीके नहीं अपना सकता हूं इसलिए मुझे टेलीफोन नहीं मिल रहा है। माननीय शास्त्री जी ने आपके सामने एक बात कही है लेकिन मैं तो आपके सामने लिखा-पढ़ी की बात कह रहा हूं। मैं यह नहीं कहता कि उच्चाधिकारी ऐसी बात सोचते हैं लेकिन कहीं कहीं नीचे का जो स्टाफ है, वह हमें अपोजीशन का मानकर हमारे साथ अनुचित व्यवहार करता है। मैं जब बदायूं पहुंच जाता हूं अपनी कांस्टीटुएन्सी में काम करने के लिए, आप समझ लीजिए उसी रोज़ से मेरा टेलीफोन खराब हो जाता है और जब तक मैं वहां रहता हूं, दो-चार बार ही टेलीफोन मिलता है, बाकी खराब ही रहता है। अगर मैं टेलीफोन पर पूछता हूं कि क्या बात है और उन्हें पता लगता है कि कश्यप बोल रहा है तो मुझे एक प्यारी सी गाली मिल जाती है। मैंने कम्पलेन्ट भी की लेकिन आजतक कोई जांच नहीं हुई। और न ही कोई पूछने आया। वहां पर जब भी मैंने इस बात की सूचना दी कि मैं आ गया हूं, 4-6 दिन रहूंगा, मेरा टेलीफोन ठीक रहे तो यह कहकर रख दिया गया कि जब तक आप यहां पर रहेंगे, टेलीफोन आउट आफ आर्डर रहेगा। मैंने यहां पर प्रिविलेज का मामला भी उठाया था। बरेली से कोई अधिकारी भी वहां पर गए थे लेकिन उनके सामने भी कहा कि ये लोकदल के हैं तो मैं कांग्रेस का हूं, इनको कैसे काम करने दूंगा? आज तक उस कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: यह बहुत सीरियस चार्ज है। (व्यवधान)

SHRI RATANSINH RAJDA (Bombay South): If a Government servant talks like that, this is a very serious charge. Action must be taken here and now.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Minister will reply. He is hearing. You wait for the reply of the Minister.

श्री जयपाल सिंह कश्यप: जो डिस्ट्रिक्ट सेन्टर्स हैं या दूसरी छोटी-छोटी जगहें हैं, वहां पर यदि आप अचानक किसी को भेजें तो पायेंगे कि वहां के कर्मचारी ट्रांजिस्टर सुन रहे हैं, मैच सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं या सो रहे हैं या ताश के पत्ते खेल रहे हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का कोई अहसास नहीं है। क्या मन्त्री जी कोई स्क्रीनिंग एक्वाड बनायेंगे जो जगह जगह जाकर जांच कर सके कि आपके कर्मचारी सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं?

इसमें एक दिक्कत और आती है। दो विभागों के बीच का मामला बन जाता है। टेलीफोने के लिए लाइन ले जानी है, उसकी खुदाई होगी और जब खुदाई होती है तो यह पता नहीं है कि यह आपके विभाग की जिम्मेदारी है, सी० पी० डब्ल्यू० डी० की जिम्मेदारी है या पी० डब्ल्यू० डी० की जिम्मेदारी है। सड़क पर खुदाई होती है, लाइन डाली जाती है। लाइन डालने के बाद मिट्टी डालकर उसको बन्द कर दिया जाता है। बरसात के दिनों में पानी आता है और वहां जमा हो जाता है और नीचे पहुंच जाता है जिससे इसका प्रभाव लाइन पर पड़ता है। सही तरीके से काम नहीं चलता है। इलाहाबाद से लेकर बदायूं तक, जितनी छोटी-छोटी जगहें हैं बरेली तक, सारी की सारी सड़कें चार-चार, पांच-पांच साल तक ऐसी रहती हैं। सिर्फ टेलीफोन को रंगना अच्छा नहीं है, उससे काम नहीं चलेगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER : At least, there is a little bit of appreciation of the Department.

श्री जयपाल सिंह कश्यप : विशेष तौर से पुलिस स्टेशन्स से लेकर, ब्लाक स्तर से लेकर छोटे कस्बों में टेलीफोन्स की ज्यादा आवश्यकता हो गई है। टेलीफोन की व्यवस्था इस तरह से डि-सेंट्रलाइज हो कि किसी भी गांव के आदमी को इसकी सुविधा मिल सके और वह दुरुस्त सुविधा हो, ताकि उसको युटिलाइज किया जा सके। क्या ऐसी सुविधा तीन से पांच मील के अन्दर उपलब्ध करायेंगे, ताकि लोगों को इसकी सुविधा मिल सके? यह व्यवस्था कब तक हो जाएगी? एक बात मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बहुत सी मिनिस्ट्रीज और सैन्ट्रल गवर्नमेंट के बीच बिलों को लेकर झंझट चल रहा है, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। बहुत से कनैक्शन कट चुके हैं, जिस की वजह से काम रुका हुआ है, कार्यालयों का काम रुका हुआ है। बहुत से मामले तय नहीं हो पाते हैं। क्या आप इनको जल्दी तय करायेंगे; ताकि सुविधा मिल सके? आज ही के नवभारत टाइम्स में निकला है कि फरीदाबाद, गाजियाबाद और वल्लभगढ़ क्षेत्र के टेलीफोन को दिल्ली से अलग किया जा रहा है, उनको सेप्रेट किया जा रहा है। यह बहुत ही अच्छा है, इससे क्षमता बढ़ेगी। जितना डिसैन्ट्रलाइज होगा उतनी एडमिनिस्ट्रेशन में सुविधा होगी। इसमें क्या-क्या फायदे होंगे और क्या-क्या नुकसान होंगे, यह कृपया बताने का कष्ट करें?

SHRI V.N. GADGIL : Sir, in the first place, I would like to say that if the hon. Member desired to have an extra connection and if he had approached me, it would have been done immediately because under the rules, an M.P. is entitled to a telephone at Delhi, one at his permanent place of residence and one more at his private accommodation.

With regard to the point raised by him and Shri Shastri earlier about what the local employees did, if they could give me the specific details, I shall certainly look into those

श्री जयपाल सिंह कश्यप : हमने सारी कम्पलेंट्स कर दी हैं। सारी लिखित हैं।

SHRI V.N. GADGIL : Did you send since I have taken over ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : You can write to the Minister.

SHRI V.N. GADGIL : What I was trying to inform the House was that some telephones did not work for some time because of the shifting of telephones and the connection was restored and since then there has not been any complaint.

Now with regard to his question as and when provision is made for villages, our accepted policy as laid down is that by 1990, every area of 5 KM on hexagonal basis will have a telephone connection and it is the target. He said about disconnection of telephones by local authorities or Governments. Whenever such occurrences are brought to the P and T Directorate, immediate action is taken and the telephone is restored. With regard to digging by various authorities, I must say, in those parts of the areas, the construction and other things are not done by us but by the local authorities, Zilla Parishad and others and we pay them compensation. The actual work is not done by us.

As regards the instruments, it is true that some of the instruments are faulty and that is why ITI has developed now a new model. It is XL 677. I am told by experts that this new model is perfect and that there will be less complaints on the basis of the fault of instrument.

He mentioned about telephones working on goodwill, and then on 'God will' and then perhaps on 'Gadgil will'. But I will certainly look into any specific cases particularly where corruption or rudeness takes place to a Member of Parliament.